

दिनांक : 29.12.2025

समय : 01:00 पी.एम.

आकाशवाणी जयपुर-अजमेर से
प्रादेशिक समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अरावली पहाड़ियों से जुड़े 20 नवम्बर के अदालत के आदेश को अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने उस आदेश को लागू करने से पहले निष्पक्ष और स्वतंत्र समीक्षा की जरूरत बताई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसके लिए सरकार को एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने को कहा है, जो खनन के पर्यावरणीय प्रभाव, परिभाषाओं की सीमाओं और संरक्षण की निरंतरता सहित अन्य मुद्दों की जांच करेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 21 जनवरी को होगी।

इस बीच, प्रदेश में आज से अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अरावली क्षेत्र वाले 20 जिलों में विशेष अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान खान, वन और पर्यावरण, राजस्व, पुलिस तथा परिवहन विभाग के सहयोग से 15 जनवरी तक जारी रहेगा। ईको सिस्टम में अरावली पर्वतमाला के महत्व और जैव विविधता संरक्षण, मरुस्थलीकरण की रोकथाम तथा भूजल रिचार्ज में इसकी भूमिका को देखते हुए ये पहल की गई है। अभियान के दौरान संवेदनशील और अन्य क्षेत्रों में अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण-वीबी-जीरामजी योजना के तहत अधिकांश राज्यों को पिछले सात वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में 17 हजार करोड़ रुपये अधिक आवंटित होने की संभावना है।

इस कानून ने 20 साल पुरानी मनरेगा योजना का स्थान लिया है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार इससे राज्यों के समग्र धन वितरण में सुधार होगा। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्य कांति घोष की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित भारत-जी राम जी का उद्देश्य सभी स्तरों पर रोजगार सृजन, पारदर्शिता, नियोजन और जवाबदेही को मजबूत करना और संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना है। संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया ये विधेयक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 61वां प्रांत अधिवेशन आज से जयपुर में हो रहा है। तीन दिन के इस अधिवेशन में 700 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें परिषद के अभियानों, वंदे मातरम् के इतिहास और महापुरुषों के जीवन को दर्शाया गया है।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई आज से फिर शुरू हो गई है। ये सुनवाई अब नियमित रूप से सप्ताह में तीन दिन होगी। मंत्री जोराराम कुमावत और विजय चौधरी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश मंत्री अपूर्वा सिंह और नारायण मीणा भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मंत्रियों के आवास पर जनसुनवाई पहले की तरह सुचारु रूप से जारी रहेगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने भी आज अपने आवास पर जनसुनवाई की।

प्रदेश में नये साल की शुरुआत तेज सर्दी और हल्की बारिश के बीच होने के आसार हैं। मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार जनवरी महीने के शुरुआती दिनों में जोधपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी अंचल में मावठ का पूर्वानुमान है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बादल भी छाये रहेंगे। बीते 24 घंटों में सीकर, दौसा, पाली, अलवर सहित कुछ स्थान शीतलहर की चपेट में हैं।

कोहरे और ठंड के प्रकोप को देखते हुए कृषि विभाग की ओर से किसानों को फसलों में हल्की सिंचाई करने और मेड़ों पर धुंआ करने की सलाह दी गई है। वहीं पशु चिकित्सकों की ओर से पशुओं को हर हफ्ते अजवाइन, गिलोय और तुलसी के पत्ते देने को कहा है।

कोहरे से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। वहीं कोहरे के कारण दृश्यता में कमी से अनेक उड़ानें रद्द की गई हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों को हवाई अड्डे पहुंचने से पहले उड़ान की ताजा स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी है। यात्रियों से हवाई अड्डे पर पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय रखने को कहा गया है।

.....

जोधपुर में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर 167 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक वंदे भारत मेटेनेंस डिपो का निर्माण किया जा रहा है। करीब 18 हजार वर्गफीट क्षेत्र में फैला ये डिपो भारतीय रेलवे का पहला डेडीकेटेड स्लीपर मेटेनेंस डिपो होगा। अगले साल जून में इसके पूरा होने की संभावना है। इसके बाद स्लीपर ट्रेनों का नियमित रख-रखाव शुरू किया जा सकेगा। इस डिपो में उन्नत तकनीक से ट्रेनों की सफाई, तकनीकी जांच और परीक्षण तथा मरम्मत की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इससे रेलगाड़ियों की परिचालन दक्षता बढ़ेगी और रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।

.....